समितियों को जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों के रूप में बदल रही सरकार

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 – अंक : 05 – अगस्त 2025

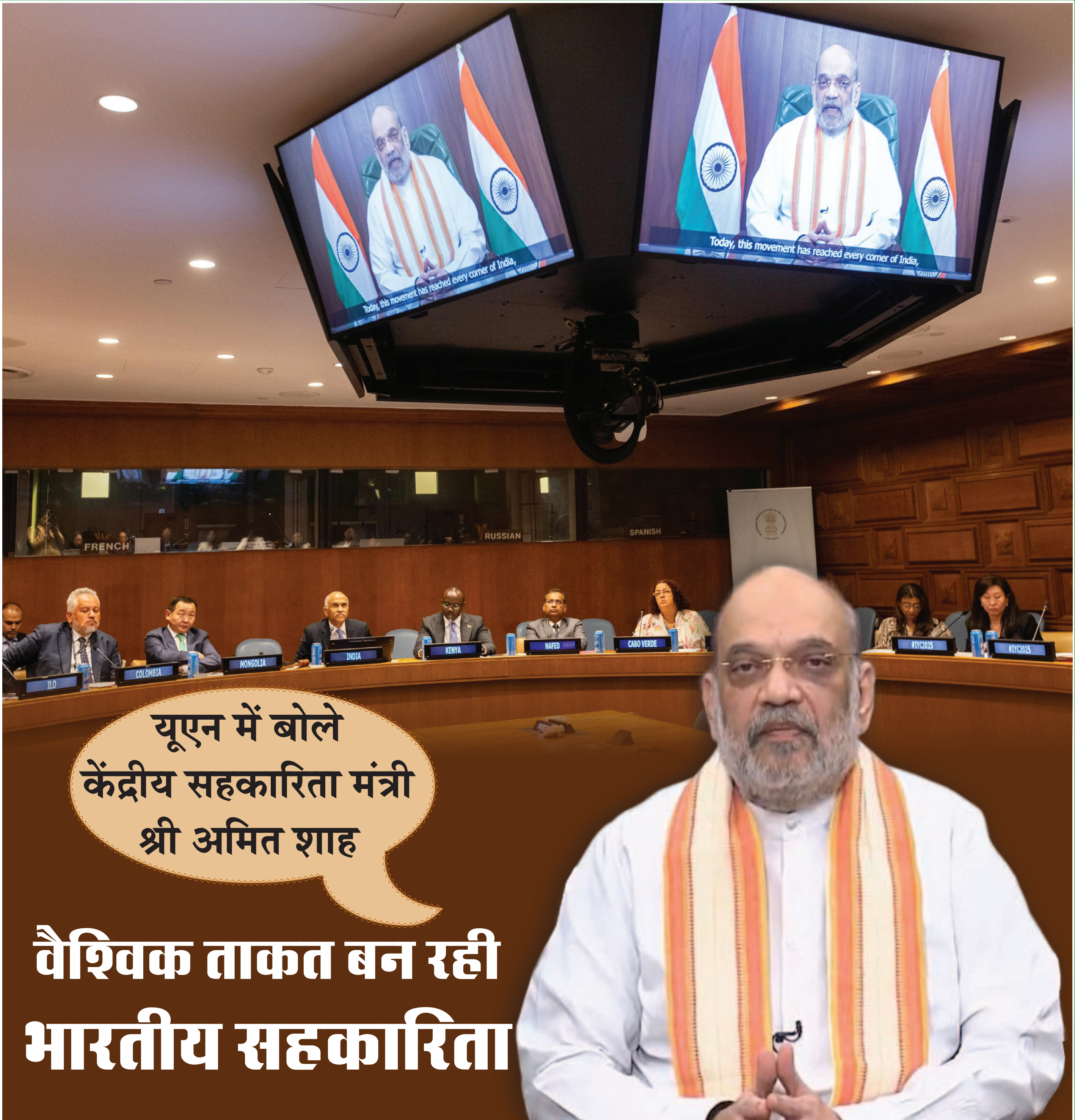

यूएन में बोले
केंद्रीय सहकारिता मंत्री
श्री अमित शाह

वैश्विक ताकत बन रही भारतीय सहकारिता

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार जागरण
अगस्त 2025, अंक 05, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. सुधीर महाजन
संपादक
राजीव शर्मा
समूह संपादक
वेद प्रकाश सेतिया

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com

प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली: 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते:

MINISTRY OF COOPERATION

NCUI हाट

CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

06

आवरण कथा

भारत की नई ताकत बन चुकी है सहकारिता

सहकारिता का विचार न केवल आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक है, बल्कि सतत और समावेशी विकास के लिए भी आवश्यक है। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है।

12

समृद्ध बिहार के लिए प्रत्येक युवा को रोजगार के प्रति सरकार प्रतिबद्ध

21वीं सदी में दुनिया का तेजी से विकास हो रहा है। पश्चिमी देशों के साथ ही पूर्वी देश भी अब विकास की दौड़ में आगे हैं। उनकी भागीदारी और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह दुनिया में पूर्वी देशों में तेजी से विकास हो रहा है, उसी तरह भारत में भी यह पूर्वी राज्यों का युग है।

देश के सभी गांवों, गरीबों व किसानों तक सहकारिता का विस्तार — 14

कनेक्टिविटी के बेहतर होने से ही अर्थव्यवस्था होगी मजबूत — 16

जल प्रवाह बढ़ाने से बदलेगी यमुना की सूरत — 20

विदेशों में बसे भारतवंशियों को अपनी विरासत पर गर्व — 21

राज्यों के विकास से ही होगा विकसित भारत का निर्माण — 22

काशी-तमिल और सौराष्ट्र तमिल संगमम से एकता का बंधन हो रहा मजबूत — 24

29

सहकारी कृषि में नए मानक स्थापित कर रहा समृद्धि एफपीओ

भारतीय सहकारी मॉडल को वैश्विक पहचान

भारतीय सहकारिता आंदोलन की जड़ें हमारे देश के सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में गहराई से समाई हुई हैं। 'वसुधैव कुटुम्बकम' के प्राचीन भारतीय लोक व्यवहार से प्रेरणा लेकर सामाजिक एकता और आपसी सहयोग से हमारी सहकारिता पोषित एवं पल्लवित हुई है। इसी चिंतन के आधार पर भारत सरकार 'सहकार से समृद्धि' के ध्येय को पूरा करने की दिशा में नीतिगत पहल, सहकारी प्रबंधन और आर्थिक सहयोग करके सहकारी समितियों के विकास को गति दे रही है। भारत के इस विजन को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ में हुए एक वैश्विक आयोजन में वीडियो संदेश के जरिए साझा किया और विश्व समुदाय को बताया कि भारत में सहकारिता समावेशी विकास, सामुदायिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में विकसित हुआ है।

सहकारिता मंत्रालय के गठन के चार वर्षों के दौरान सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान समय में देशभर की 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियां कृषि क्षेत्र के अलावा ऋण, आवास, मार्केटिंग, डेयरी, मत्स्य पालन सहित डिजिटल सेवाओं, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार आदि 30 से अधिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं और ग्रामीणों को ऋण, रोजगार एवं स्वरोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़कर बढ़ावा दे रही हैं।

नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) के जरिए ये सहकारी समितियां देश के छोटे और सीमान्त किसानों को भी सीधे तौर पर वैश्विक बाजारों से जोड़ रही हैं। हमारे देश के सहकारी उत्पाद अब ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात के जरिए वैश्विक स्तर तक पहुंचकर अपनी धाक जमा रहे हैं। नवाचार और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं इन समितियों के जरिए देशभर में सहकारिता से सीधे तौर पर जुड़े 32 करोड़ सक्रिय सदस्यों व स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण हो रहा है, जिससे बुनियादी स्तर विकास के साथ सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है। इन्हीं उद्देश्यों से सरकार सहकारी समितियों को अधिक समावेशी बनाने पर जोर दे रही है।

दरअसल, भारत में सहकारी समितियां उपेक्षित, वंचित और साधनविहीन वर्गों और स्थानीय समुदायों के बीच एक ऐसे मजबूत संबल के रूप में स्थापित हो रही हैं, जो इन जरूरतमंद लोगों को संसाधनों तक पहुंचाने, उनकी आजीविका सुरक्षित करने और अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाकर अनगिनत लोगों के जीवन में बदलाव का माध्यम बन रहीं हैं। सहकारी समितियां स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों के आधार पर काम कर रही हैं और समाज के वंचित वर्गों के हितों की सेवा कर रही हैं। इन समितियों के सदस्य अपने संसाधनों को एकत्रित करके साझा लाभ प्राप्त करने के लिए उनका सामूहिक उपयोग कर रहे हैं और सामुदायिक कल्याण के जरिए सामाजिक विकास और समृद्धि को चरितार्थ कर रहे हैं। ■

जय सहकार

हमें गर्व है कि पिछले 11 साल में देश ने एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है, जो पारदर्शी और संवेदनशील होने के साथ-साथ लोगों की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप है। हमारी सरकार भारतवर्ष के नव-निर्माण में जुटी है, जिसमें पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक देश का कोई भी हिस्सा विकास की धारा से अछूता नहीं है।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

एक समय में लोग कहते थे, 'सहकारिता का फ्यूचर नहीं है', आज मैं कहता हूँ 'सहकारिता का ही फ्यूचर है'। छोटी-छोटी पूँजियों को जोड़कर बड़ा उद्यम खड़ा करने की क्षमता सिर्फ सहकारिता के पास है। नेशनल कोऑपरेटिव पालिसी से टूरिज्म, टैक्सी, इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी सहकारी समितियां बन पाएंगी।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी गई। 2025 से 6 साल तक के लिए लागू होगी योजना, इस पर हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे 100 जिलों के 1.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

श्री कृष्ण पाल गूर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

देश और समाज के सर्वांगीण एवं समावेशक विकास में सहकारीता का बहुमूल्य योगदान है। नया मंत्रालय का गठन के बाद देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं।

श्री दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

ह्रराष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025ह्र महिलाओं और युवाओं को सहकारी आंदोलन का सशक्त हिस्सा बनाने के लिए व्यापक रणनीति लेकर आई है। नीति का उद्देश्य महिलाओं, युवाओं, एससी/एसटी और दिव्यांगजनों की भागीदारी को संस्थागत रूप से सुनिश्चित करना है। तकनीकी प्रशिक्षण, नेतृत्व में भागीदारी, जागरूकता अभियान और मॉडल बायलॉज के माध्यम से सहकारिता अब सबकी साझेदारी का माध्यम बनेगी। यह नीति एक समावेशी, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की दिशा में ठोस कदम है।

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

'मन की बात' के 124वें एपिसोड में बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

विज्ञान के प्रति बढ़ रहा देशवासियों का रुझान

सहकार जागरण टीम

21वीं सदी के भारत में आज विज्ञान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। एक नई ऊर्जा के साथ विज्ञान आगे बढ़ रहा है। हाल ही में शुभांशु शुक्ला के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापसी को लेकर खूब चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े, खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' के 124वें एपिसोड में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया।

अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग से देश में बढ़ते वैज्ञानिक रुझान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल हासिल कर भारत का नाम रोशन किया। गणित की दुनिया में भी भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया। आस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे छात्रों ने तीन गोल्ड, दो सिलवर और एक ब्रोंज मेडल हासिल किया। प्रधानमंत्री ने अगस्त में मुंबई में होने वाले एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र और वैज्ञानिक भाग लेंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है।

बच्चों के नवाचार को बढ़ावा देने वाले 'इंस्पायर मानक' अभियान का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बताया कि इसमें हर स्कूल से पांच बच्चे चुने जाते हैं। और हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और

- **आत्मनिर्भर भारत, स्पेस स्टार्टअप्स, स्वदेशी आंदोलन, स्वच्छता, और लोकल बिजनेस पर विशेष जोर**
- **श्री मोदी ने विज्ञान, पर्यावरण और विरासत को महत्व देते हुए देशवासियों को दी प्रेरणा**

चंद्रयान-3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में स्पेस स्टार्टअप्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पांच साल पहले 50 से भी कम स्टार्टअप थे और आज 200 से अधिक सिर्फ अंतरिक्ष क्षेत्र में हो गए हैं।

यूनेस्को द्वारा महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु के एक मराठा किले को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर किले से इतिहास का एक-एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है। सल्हेर का किला, जहां मुगलों की हार हुई। शिवनेरी, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, इसे दुश्मन भेद न सके। खानदेरी का किला, समुद्र के बीच बना अद्भुत किला। प्रतापगढ़ का किला, जहां अफजल खान पर जीत हुई, उस गाथा की गूंज आज भी किले की दीवारों में समाई है। गुप्त सुरंगों वाला विजयदुर्ग किला छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता का प्रमाण है। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही अद्भुत किले हैं, जिन्होंने आक्रमण झेले, खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी भी झुकने नहीं दिया।

11 अगस्त 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में 18 वर्षीय खुदीराम बोस को अंग्रेजों द्वारा फांसी देने की घटना को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खुदीराम बोस ने बलिदान देकर अपने देशप्रेम की कीमत चुकाई। फांसी के फंदे की ओर जाने के दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनके साहस ने पूरे देश को झकझोर दिया। ऐसे ही अनगिनत बलिदानों व सदियों की तपस्या के बाद हमें आजादी मिली थी। देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था। अगस्त का महीना तो क्रांति का महीना है। ■

संयुक्त राष्ट्र में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हिंदी में दिया भाषण

भारत की नई ताकत बन चुकी है सहकारिता

सहकार जागरण टीम

सहकारिता का विचार न केवल आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक है, बल्कि सतत और समावेशी विकास के लिए भी आवश्यक है। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। सहकारिता भारत की नई ताकत बन चुकी है और अब यह डिजिटल सेवाओं, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वित्तीय समावेशन

सेवा, रोजगार और नवाचार का आधार बन रही सहकारिता, हर भारतीय बन रहा विकास का लाभार्थी

डिजिटल सेवाओं और ग्रामीण विकास कार्यों में अहम भूमिका निभा रही सहकारिता

जैसे क्षेत्रों में नवाचार और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम के रूप में पहचानी जा रही है। इन विचारों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए व्यक्त किया। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में हुए वैश्विक आयोजन में श्री शाह ने हिंदी में कहा, 'हजारों वर्षों से सहकारिता भारतीय मूल्यों की आत्मा रही है।' वहीं, अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ सहकारिता को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सहकारिताओं ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और महिलाओं, युवाओं और वंचितों को सक्रिय भागीदार और हितधारक बनाया है। हमारे देश में सहकारिता अब केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि विविध क्षेत्रों में बदलाव की मिसाल बन चुकी है। श्री शाह ने कहा, 'भारत में, सहकारिता एक जीवंत और समुदाय-संचालित प्रणाली है जो कृषि से लेकर वित्त तक, उपभोग से लेकर

निर्माण तक, और ग्रामीण सशक्तिकरण से लेकर डिजिटल समावेशन तक, हर क्षेत्र को आपसी सहयोग और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से शामिल करती है।'

देश में ग्रामीण विकास का एक नया रोल मॉडल बन रहीं सहकारी समितियों के महत्व पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा, 'भारत में सहकारी समितियां अब अपनी पारंपरिक सीमाओं से आगे निकल गई हैं और डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ऊर्जा, जैविक खेती और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में नवाचार और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन गई हैं।' ये समितियां पारंपरिक सीमाओं को लांघकर अत्याधुनिक नवप्रवर्तक बन गई हैं। इन समितियों ने किसानों को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़ा है और अब ये स्थानीय किसानों-उत्पादकों को ग्लोबल स्तर तक पहचान दिला रही हैं। सहकारी समितियां कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात करके किसानों की समृद्धि की राह बना रही हैं। श्री शाह ने कहा, 'सहकारिता की अनूठी ताकत इस तथ्य में निहित है कि यह स्थानीय स्तर पर लाभ प्रदान करती है और साथ ही ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम भी बनती है।' उन्होंने कहा कि किसानों को वैश्विक बाजारों से सीधे जोड़ने और निर्यात से होने वाले लाभ में उन्हें उचित हिस्सा मिले, इसके लिए तीन बहु-राज्य सहकारी समितियां - भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल), राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना की गई है।

> भारत में सहकारिता एक जीवंत और समुदाय-संचालित प्रणाली है जो कृषि से लेकर वित्त तक, उपभोग से लेकर निर्माण तक और ग्रामीण सशक्तीकरण से लेकर डिजिटल समावेशन तक हर क्षेत्र को आपसी सहयोग और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से शामिल करती है।
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

समावेशी विकास का मॉडल बनी भारतीय सहकारिता

श्री शाह ने सहकारिताओं की प्रभावशीलता बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार और सहकारिता मंत्रालय के विभिन्न पहलों पर जोर देते हुए कहा

कि वर्ष 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद विभिन्न विकासात्मक सुधारों के जरिए भारत का सहकारी मॉडल वैश्विक मंच पर समावेशी विकास की हमारी अवधारणा को एक स्पष्ट और मजबूत पहचान प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का 'सहकार से समृद्धि' का विजन सहकारी आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में रूपांतरित कर रहा है और भारत के गांवों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बना रहा है। श्री शाह ने कहा कि भारत की सहकारिताएं न केवल सफल हैं, बल्कि टिकाऊ भी हैं। सहकारी संस्थाएं संसाधनों के पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सामूहिक उपयोग पर आधारित मॉडलों को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे जैविक खेती, सामुदायिक बायोगैस संयंत्र और अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधन दक्षता को बढ़ावा मिल रहा है।

डिजिटल नवाचारों से अधिक समावेशी बनीं समितियां

डिजिटल नवाचारों ने सहकारी समितियों को और अधिक समावेशी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता सेवा, रोजगार और नवाचार का आधार बन रही है और यही मॉडल समावेशी विकास को वैश्विक पहचान दिला रहा है, जिससे हर भारतीय विकास का भागीदार और लाभार्थी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियों से जुड़े 32 करोड़ सदस्य सक्रिय हैं और यह सहकारी मॉडल समावेशी विकास को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला रहा है। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि सहकारिता के सिद्धांत, मूल्य और जन-केंद्रित दृष्टिकोण इसे मानव-केंद्रित विकास के सबसे प्रभावशाली मॉडलों में से एक बनाते हैं। श्री शाह ने कहा, भारत में सहकारिताएं 'साझेदारी, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित एक सांस्कृतिक चेतना पर आधारित हैं, जो हमें 'मैं' से 'हम' के मार्ग पर ले जाती हैं और सामूहिक शक्ति की शक्ति का प्रमाण हैं'। उन्होंने कहा, 'ये संस्थाएं उत्पादकों को स्थानीय से वैश्विक बनाने की दिशा में शक्तिशाली कदम हैं।'

सहकारिता का राष्ट्रीय केंद्र बनेगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय

देश में नई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदमों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत में सहकारिता अपनी पारंपरिक सीमाओं से आगे निकल ग्रामीण समाज को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बना रही है। भारत के सहकारी आंदोलन को पारदर्शी, जवाबदेह और भविष्योन्मुखी बनाने के लिए नई कोऑपरेटिव पॉलिसी का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और नेतृत्व विकास के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। श्री शाह ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भी सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित हो रही है। यह योजना न सिर्फ खाद्य सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य और संगठित बाजार भी उपलब्ध कराती है। ■

- भारत में सहकारिता अब कृषि तक सीमित नहीं
- देश में 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियों से जुड़े हैं 32 करोड़ सक्रिय सदस्य
- सहकारी समितियों ने किसानों को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़ा
- उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात के जरिए स्थानीय से ग्लोबल स्तर तक पहुंच रहे हैं उत्पादक
- डिजिटल नवाचार जैसे एआई, एम-स्ट्राइप्स आदि ने सहकारी समितियों को अधिक समावेशी बनाया
- हमारा सहकारी मॉडल समावेशी विकास को दिला रहा वैश्विक पहचान

ग्रामीण सशक्तिकरण और विकास का आधार बनी सहकारिता

श्री शाह ने सहकारिता को आत्मनिर्भरता का माध्यम और एक ऐसी प्रणाली बताया जो स्थानीय स्तर पर लाभ देती है और ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को सम्मानजनक आजीविका का अवसर प्रदान करती है। भारत में सहकारिता केवल कृषि या उपभोक्ता क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वित्त, निर्माण, ग्रामीण सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और लोकतांत्रिक भागीदारी तक फैली हुई है। उन्होंने कहा कि तकनीकी नवोन्मेष के माध्यम से सहकारी संस्थाएं और अधिक समावेशी बन रही हैं। सहकारिता डिजिटल सेवाओं, जैविक खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सतत और समावेशी विकास का मॉडल बन चुकी है। श्री शाह ने कहा कि सहकारी समितियों ने बाजार पहुंच के जरिए टिकाऊ और लाभदायक कृषि के अवसर प्रदान किए हैं और अब वे सतत विकास की दिशा में नए रास्ते तलाश रही हैं। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था और इसका आधिकारिक शुभारंभ भी भारत में ही प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया था। श्री शाह ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहकारी समितियों की भूमिका पर जोर देते हुए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कथन को दोहराया, 'भारत का मानना है कि सहकारिताएं वैश्विक सहयोग में नई ऊर्जा ला सकती हैं। विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए, जहां विशेष विकास मॉडल की आवश्यकता है, सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए, हमें नए विचारों और वैश्विक सहयोग के नए मार्गों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किया शुभारंभ

कच्छ में बनी देश की पहली नमक कोऑपरेटिव सोसाइटी

सहकार जागरण टीम

जीसीएमएमएफ और सरहद डेयरी ने संयुक्त रूप से किया श्री कच्छ जिला दरिया कंथा विस्तरणी मीठा उत्पादक और वहेचन सहकारी मंडली लिमिटेड का गठन

गुजरात के कच्छ के नमक उत्पादकों को संगठित करने, उन्हें बाजार से जोड़ने, उनके लिए इनपुट सेवाएं उपलब्ध कराने और उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए पहली बार नमक क्षेत्र में सहकारी समिति का गठन किया गया है। इस समिति के माध्यम से नमक उत्पादन से होने वाला मुनाफा सीधे उन श्रमिकों और उत्पादकों तक पहुंचेगा जो कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। कच्छ के नमक उत्पादकों को सहकारी ढांचे के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में यह क्रांतिकारी कदम है। यहां देश के कुल नमक उत्पादन का करीब 87 प्रतिशत उत्पादन होता है।

नमक उत्पादकों के सशक्तीकरण के इस ऐतिहासिक कदम की शुरुआत गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) और सरहद डेयरी ने की है। दोनों के संयुक्त प्रयास से श्री कच्छ जिला दरिया कंथा विस्तरणी मीठा उत्पादक और वहेचन सहकारी मंडली लिमिटेड का गठन हुआ है। जीसीएमएमएफ ही अमूल ब्रांड नाम से दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पादों का कारोबार करती है जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुजरात के आणंद में आयोजित एक कार्यक्रम में देश की पहली नमक सहकारी समिति का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा, 'यह समिति सहकारिता आंदोलन के एक नए युग की शुरुआत है। कच्छ जिला नमक सहकारी समिति एक मॉडल सहकारी समिति के रूप में कार्य करेगी, जो पारंपरिक नमक

उत्पादकों (अगरियाओं) को संगठित कर उन्हें अमूल जैसे प्रभावशाली सहकारी ढांचे से जोड़ने का काम करेगी। नमक उत्पादन देश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो अब तक सहकारी ढांचे से जुड़ा नहीं था, लेकिन अब यह कमी पूरी हो गई है।' उन्होंने इस पहल के पीछे प्रमुख प्रेरणाशक्ति रहे हुंबल भाई का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि उनका प्रयास इस समिति की आधारशिला बना।

कच्छ के रण में सदियों से नमक उत्पादन से जुड़ा अगरिया समुदाय अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कार्य करता है। समाज के वंचित वर्गों से आने वाले इस समुदाय को अब तक बिचौलियों और असंगठित व्यवस्था के कारण अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता था। अगरिया समुदाय के सदस्यों को एक साझा सहकारी मंच पर लाकर यह समिति उन्हें उचित मूल्य, लाभ में हिस्सेदारी और संस्थागत समर्थन प्रदान करेगी जिससे उनकी पारंपरिक आजीविका को नई ताकत मिलेगी। सहकारिता मॉडल के अंतर्गत उन्हें सामाजिक सुरक्षा और एक सम्मानजनक जीवन की दिशा में भी समर्थन मिलेगा। कच्छ नमक सहकारी समिति के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि नमक उत्पादन से जुड़े सभी मजदूरों को संरचित और सामुदायिक नेतृत्व वाली व्यवस्था के माध्यम से न केवल स्थायी आय प्राप्त हो, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आए।

चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। देश के कुल नमक उत्पादन में कच्छ का योगदान 63 प्रतिशत है। इसकी वजह से गुजरात नंबर एक नमक उत्पादक राज्य है जो कुल 87.4 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादन में दूसरे नंबर पर राजस्थान (6.7 प्रतिशत) और तीसरे पर तमिलनाडु (4.7 प्रतिशत) का स्थान है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दमन व दीव का स्थान है जो देश के नमक उत्पादन में कुल 1.2 प्रतिशत का योगदान देते हैं। अरब सागर के तटीय इलाके पर स्थित कच्छ का नमक उत्पादन में विशेष महत्व है। यहां का अगरिया समुदाय पारंपरिक रूप से इसके

- **कच्छ के 77 हजार से ज्यादा उत्पादकों को इस समिति से मिलेगा लाभ, शुरुआत में 3,000 अगरिया नमक कोऑपरेटिव से जुड़े**
- **अभी 19,000 करोड़ रुपए का है भारत का नमक उद्योग जिसके 2034 तक बढ़कर 34,000 करोड़ रुपए हो जाने का है अनुमान**

उत्पादन से जुड़ा है। नमक की खपत खाने और औद्योगिक क्षेत्र दोनों में होती है। भारत में लगभग 74 लाख टन नमक की घरेलू खपत और 125 लाख टन की औद्योगिक खपत होती है। भारत में संगठित नमक उत्पादन की संभावनाएं बहुत अधिक है। देश में इसके उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आजादी के समय 1947 में भारत नमक का आयात करता था और तब मात्र 19 लाख टन उत्पादन हुआ था। अब भारत इसका निर्यात करता है। 2022-23 में रिकॉर्ड 39.11 लाख टन नमक का उत्पादन देश में हुआ था। वर्ष 2024 में भारतीय नमक बाजार 9,000 करोड़ रुपए का था, जिसके वर्ष 2034 तक लगभग दोगुना होकर 35,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

शुरुआत में इस समिति से 3,000 से ज्यादा अगरिया जुड़े हैं। उनके द्वारा उत्पादित नमक की यह समिति सीधी खरीद करेगी, उन्हें प्रोसेस्ड किया जाएगा और जीसीएमएमएफ के मजबूत नेटवर्क के तहत बेचा जाएगा। जीसीएमएमएफ द्वारा डेयरी क्षेत्र में अमूल की सफलता की कहानी को नमक क्षेत्र में भी दोहराए जाने की उम्मीद है। इस मॉडल को बाद में राजस्थान, तमिलनाडु और अन्य नमक उत्पादक राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। अमूल डेयरी मॉडल से प्रेरणा लेते हुए यह सहकारी संस्था जीसीएमएमएफ के व्यापक वितरण नेटवर्क के माध्यम से उत्पादकों को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग से सीधे जोड़ेगी। इससे अगरिया लोगों को सदस्यों के रूप में संगठित किया जाएगा, जिससे उन्हें शोषणकारी आपूर्ति श्रृंखलाओं और कर्ज के जाल से निकलने में मदद मिलेगी।

नमक आयुक्त की एक रिपोर्ट के अनुसार, कच्छ के 77,000 से अधिक अगरिया आजीविका के लिए नमक उद्योग पर निर्भर हैं। इनमें से ज्यादातर दूरदराज के इलाकों के हैं जहां काम करने की परिस्थितियां कठोर हैं। लगभग 88 प्रतिशत छोटे नमक किसान हैं जिनके पास 10 एकड़ से कम जमीन है। इसकी वजह से अक्सर उनके पास सौदेबाजी की शक्ति या आधुनिक प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे का अभाव होता है। भारत का नमक उद्योग मजबूत है लेकिन उत्पादक स्तर पर कम संगठित है। विशाल तटीय संसाधनों और बढ़ती वैश्विक मांग के साथ सहकारी ढांचा इस क्षेत्र को मजबूत और इसके उत्पादकों को समृद्ध बनाएगा। ■

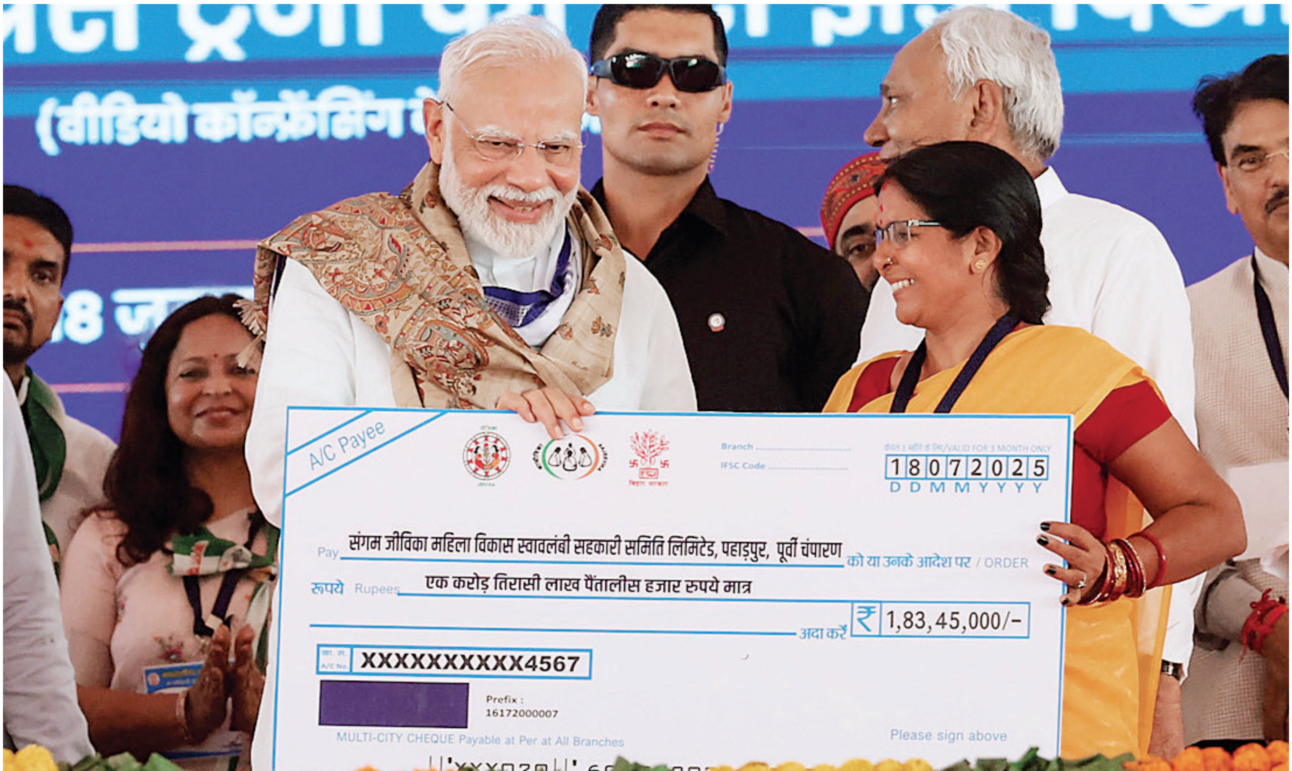

बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बोले

समृद्ध बिहार के लिए प्रत्येक युवा को रोजगार के प्रति सरकार प्रतिबद्ध

- **7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन**
- **पूर्व का मोतिहारी पश्चिम के मुंबई जैसा और गया में गुड़गांव जैसे अवसर प्राप्त होंगे**

सहकार जागरण टीम

21वीं सदी में दुनिया का तेजी से विकास हो रहा है। पश्चिमी देशों के साथ ही पूर्वी देश भी अब विकास की दौड़ में आगे हैं। उनकी भागीदारी और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह दुनिया में पूर्वी देशों में तेजी से विकास हो रहा है, उसी तरह भारत में भी यह पूर्वी राज्यों का युग है। यह विचार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए व्यक्त किया। भविष्य में मोतिहारी का विकास मुंबई की तरह करने की बात कहते हुए श्री मोदी ने गया में गुरुग्राम जैसे अवसर, पटना में पुणे जैसा औद्योगिक विकास और संथाल परगना में सूरत जैसा विकास सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी और जाजपुर में जयपुर की तरह पर्यटन का विकास होगा और बीरभूम के लोग बेंगलुरु के लोगों की तरह प्रगति करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चंपारण की भूमि है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस भूमि ने एक इतिहास रचा है। इसी भूमि ने महात्मा गांधी को नई दिशा दी। इस भूमि से मिली प्रेरणा अब बिहार के नए भविष्य को आकार देगी।

श्री मोदी ने कहा कि राज्य में आज तीव्र प्रगति संभव है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकारें हैं।

प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों के दृढ़ निश्चय

की प्रशंसा की और इसे एक ऐसी भूमि बताया जहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। बिहार की प्रगति का श्रेय राज्य की माताओं और बहनों की शक्ति तथा दृढ़ संकल्प को देते हुए, श्री मोदी ने कहा कि बिहार की महिलाएं अपनी सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम के महत्व को भली-भांति समझती हैं। बिहार में लगभग 3.5 करोड़ महिलाओं के जन-धन खाते हैं। सरकारी योजनाओं का धन अब सीधे इन खातों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

'बिहार की प्रगति भारत की प्रगति के लिए आवश्यक है' को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि बिहार तभी आगे बढ़ेगा, जब उसके युवा आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक समृद्ध बिहार और प्रत्येक युवा के लिए रोजगार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में पहली बार रोजगार की आकांक्षा रखने वालों की सहायता के लिए एक बड़ी योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत, किसी निजी कंपनी में पहली नियुक्ति पाने वाले युवाओं को केंद्र सरकार द्वारा 15,000 रुपए दिए जाएंगे। मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने बताया कि इसके तहत बिहार में लाखों लोगों को ऋण प्रदान किया गया है। बिहार के माओवादी इलाकों के नक्सलमुक्त होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे अब इन इलाकों के युवा बड़े सपने देखने लगे हैं। बिहार की धरती से ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह एक नया भारत है - एक ऐसा भारत जो शत्रुओं को दंड देने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जमीन और आसमान, दोनों ओर से सैन्य प्रहार करता है। आज उस ऑपरेशन की सफलता पूरी दुनिया देख रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में न तो क्षमता की कमी है और न ही संसाधनों की और आज बिहार के संसाधन ही उसकी प्रगति के माध्यम बन रहे हैं। सरकार के प्रयासों के बाद मखाना की कीमतों में हुई वृद्धि और इस क्षेत्र को आगे भी अधिक सहयोग देने के लिए मखाना बोर्ड के गठन का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने बिहार की

कृषि समृद्धि के उदाहरण के रूप में कई प्रमुख उत्पादों - केला, लीची, मिर्चा चावल, कतरनी चावल, जदालू आम और मघई पान का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि ये और कई अन्य उत्पाद बिहार के किसानों और युवाओं को वैश्विक बाजारों से जोड़ेंगे।

किसानों की उपज और आय बढ़ाने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत, देश भर के किसानों को लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। अकेले मोतिहारी में ही 5 लाख से ज्यादा किसानों को इस योजना के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त हुई।

प्रधानमंत्री ने सरकार का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहा कि हर पिछड़े व्यक्ति को प्राथमिकता, चाहे वह पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग, वे सरकार की प्राथमिकताओं के केंद्र में हैं।

देश के सीमावर्ती गांवों व पिछड़े छेत्रों के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए श्री मोदी ने लंबे समय से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग को पूरा करने का जिक्र करते हुए कहा कि जनजातीय समुदायों में सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के लिए जनमन योजना शुरू की गई और इसके तहत उनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री ने इसी विजन के साथ जुड़ी एक नई प्रमुख पहल की घोषणा की: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, कृषि की दृष्टि से समृद्ध लेकिन उत्पादकता और किसान आय में पिछड़े 100 ज़िलों की पहचान की जाएगी और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इन ज़िलों के किसानों को इस योजना के तहत लक्षित सहायता मिलेगी। इससे देश भर के लगभग 1.75 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ होगा, जिनमें बिहार का एक बड़ा हिस्सा शामिल है।

श्री मोदी ने हजारों करोड़ रुपये की रेल और सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का जिक्र करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से बिहार के लोगों की सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने देश भर में चार अलग-अलग मार्गों पर अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। मोतिहारी-बापूधाम से सीधे दिल्ली के आनंद विहार तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का जिक्र कर प्रधानमंत्री ने कहा कि मोतिहारी रेलवे स्टेशन का आधुनिक सुविधाओं और नए रूप के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है। दरभंगा-नरकटियागंज रेल लाइन के दोहरीकरण से इस मार्ग पर यात्रा सुविधा में अत्यधिक सुधार होगा।

भारत की आस्था और सांस्कृतिक विरासत के साथ चंपारण के गहरे जुड़ाव पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि राम-जानकी पथ मोतिहारी के सत्तरघाट, केसरिया, चकिया और मधुबन से होकर गुजरेगा। सीतामढ़ी से अयोध्या तक विकसित की जा रही नई रेल लाइन चंपारण के श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अयोध्या आने में सक्षम बनाएगी। इन पहलों से बिहार में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ■

जयपुर में 'सहकार एवं रोजगार उत्सव' में बोले श्री अमित शाह

देश के सभी गांवों, गरीबों व किसानों तक सहकारिता का विस्तार

सहकार जागरण टीम

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के चार वर्ष के भीतर हमने 61 पहलों के जरिये सहकारिता को मजबूत किया है। दो लाख नए पैक्स बनाने के संकल्प के तहत 40 हजार पैक्स बना लिए गए हैं। देश के सभी पैक्स का कंप्युटरीकरण कर लिया गया है और सभी राज्यों ने पैक्स के मॉडल बायलॉज स्वीकार कर लिए हैं। इन उपलब्धियों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में 'सहकार एवं रोजगार उत्सव' के दौरान देशवासियों से साझा किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के हर गांव, गरीब और किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ चार साल पहले सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। वर्तमान में देश में आठ लाख 50 हजार सहकारी समितियों के जरिए 31 करोड़ से अधिक देशवासी सहकारिता से जुड़े हुए हैं और इस तरह भारत के 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाले 100 साल सहकारिता के होंगे। सहककारी क्षेत्र के जरिए ही विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत देश के सभी गावों को कवर करते हुए ब्लॉक स्तर पर गोदाम बनाए जा रहे हैं। सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बीज संवर्धन, ऑर्गेनिक उत्पादों और निर्यात के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

- राजस्थान के आठ हजार से अधिक युवाओं को दिए गए नौकरियों के नियुक्ति पत्र
- श्री शाह ने 24 अन्न भंडारण गोदामों और 64 मिलेट आउटलेट्स का किया वर्चुअल लोकार्पण
- गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 गोपालकों को 12 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया

(एनसीईएल) के रूप में तीन नई बहुराज्यीय सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं। सहकारी क्षेत्र के अहम योगदान का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के धान और गेहूं की खरीद में सहकारिता का लगभग 20 प्रतिशत योगदान है, 35 प्रतिशत उर्वरक व 30 प्रतिशत चीनी का उत्पादन भी सहकारी क्षेत्र में होता है और 20 प्रतिशत से अधिक उचित मूल्य की दुकानें भी सहकारिता के जरिए ही चलती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नॉफेड और एनसीसीएफ के ऐप पर पंजीकरण करने वाले किसानों के दलहन, तिलहन व मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद करने की गारंटी दी है।

देश के कृषि विकास में राजस्थान का बड़ा योगदान

श्री शाह ने राजस्थान के विभिन्न जिलों के आठ हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने 24 अन्न भंडारण गोदाम और 64 मिलेट आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण भी किया और गोपाल

क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण किया और दुग्ध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम भी प्रदान किए। साथ ही, श्वेत क्रांति 2.0 झ प्राइमरी डेयरी कोआपरेटिव सोसाइटी (पीडीसीएस) ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम अभियान के तहत सफलता की कहानियों के संकलन तथा वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सफलता की कहानियों के संकलन का विमोचन भी किया। श्री शाह ने दो उत्कृष्ट प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश के कृषि विकास में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। देश में ग्वार का 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन राजस्थान में हो रहा है और सरसों का 46 प्रतिशत, बाजरे का 44 प्रतिशत, तिलहन का 22 प्रतिशत और मिलेट्स का 15 प्रतिशत उत्पादन करके राजस्थान देश में अग्रणी है। मूंगफली का 18 प्रतिशत उत्पादन करके राजस्थान इसके उत्पादन में देश में दूसरे नंबर पर और ज्वार, चना, दलहन और सोयाबीन के उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि मोदी ने बीते 11 साल के अपने कार्यकाल के दौरान गेहूं की एमएसपी में 73 प्रतिशत, चने में 82 प्रतिशत, सरसों में 95 प्रतिशत और मूंगफली की एमएसपी में 82 प्रतिशत वृद्धि की है।

राज्य में मजबूत हुई सहकारिता

श्री शाह ने कहा कि राजस्थान को पूरा देश ऊंटों की भूमि के तौर पर जानता है। सहकारिता के माध्यम से ऊंटों की नस्ल के संरक्षण और ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणों पर रिसर्च हो रहा है। इससे आगामी दिनों में ऊंटों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की मौजूदा सरकार ने काफी कम समय में ढेर सारे काम किए हैं। सहकारिता मंत्रालय की सभी पहल को लागू किए जाने में राजस्थान को देश के शीर्ष राज्यों में शामिल किया है और इन प्रयास से राज्य में सहकारिता मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध हुए और तीन लाख करोड़ रुपए के अनुबंध पर काम भी शुरू हो गया है। सरकार ने पेट्रोल-डीजल के वैट में कटौती की, 450 रुपए में एलपीजी सिलिंडर दिया। राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला बैराज से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर करके बहुत सारे गांवों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल की आपूर्ति की शुरू की गई है।

राजस्थान की भूमि ने वीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, दुगार्दास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, महारानी पद्मिनी, पन्ना धाय और भामाशाह जैसे दानवीरों को जन्म दिया। श्री शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा में राजस्थान का महत्त्वपूर्ण योगदान है और यहां से बडी संख्या में लोग सेना में जाते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित निर्मल सिंह सेखों की जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्री शाह ने कहा कि निर्मल सिंह सेखों ने अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिए अतुल्य शौर्य और बलिदान का परिचय दिया। ■

समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश 11वें नंबर से छलांग लगाकर अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। श्री मोदी ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने और देश को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा काम किया है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, पांच किलो मुफ्त अनाज और पांच लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज और मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था की। पिछली सरकार के दौरान जहां देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था, वहीं जब उरी में हमला हुआ तो सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक की और पहलगाम में हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए। श्री शाह ने कहा कि पूरी दुनिया को भारत ने एक मजबूत संदेश दिया है कि कोई भी हमारे नागरिकों, सेना और देश की सीमा के साथ छेड़खानी न करे, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। सरकार ने यह संदेश देकर एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया है।

दुर्गापुर में आयोजित एक समारोह में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कनेक्टिविटी के बेहतर होने से ही अर्थव्यवस्था होगी मजबूत

सहकार जागरण टीम

- घरेलू गैस कनेक्शनों की संख्या में हुई अभूतपूर्व वृद्धि
- दुनिया में हो रही विकसित भारत के संकल्प की चर्चा
- दुर्गापुर में 5400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

भारत के विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। देश में हो रहे बदलावों से विकसित भारत की नींव रखी जा रही है। 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के अनुरूप और पश्चिम बंगाल के हो रहे विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5400 करोड़ रुपए से अधिक की तेल एवं गैस, बिजली, सड़क व रेल से जुड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे।

भारत के विकास में इस्पात नगरी के रूप में विख्यात दुर्गापुर के योगदान की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन इस भूमिका को और सशक्त करने का अवसर है। आज शुरू की गई परियोजनाएं क्षेत्र में संपर्क को और बेहतर बनाएंगी व परिवहन तथा अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देंगी। इससे दुर्गापुर की इस्पात नगरी के रूप में पहचान और मजबूत होगी। क्षेत्र के हवाई अड्डों को उड़ान योजना के साथ जोड़ने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने बताया कि पिछले वर्ष में ही पांच लाख से अधिक यात्रियों ने उड़ान योजना के माध्यम से यात्रा की है। इस तरह की बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इससे न केवल

देश में हो रहे सामाजिक, डिजिटल व बुनियादी ढांचा परिवर्तनों पर बल देते हुए श्री मोदी ने गरीबों के लिए चार करोड़ से अधिक पक्के घर, करोड़ों शौचालय, 12 करोड़ से अधिक नल के पानी के कनेक्शन, हजारों किलोमीटर नई सड़कें, नई रेल लाइनें, छोटे शहरों में हवाई अडडे और हर गांव व घर तक व्यापक इंटरनेट पहुंच पर प्रकाश डाला और कहा कि इसका लाभ पश्चिम बंगाल समेत देश के अन्य राज्यों को भी मिल रहा।

पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह राज्य बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनों के संचालन में अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने कोलकाता मेट्रो के तेजी से विस्तार, रेल पटरियों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण पर प्रकाश डाला और कहा कि राज्य में कई स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और बड़ी संख्या में रेलवे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। इससे पश्चिम बंगाल के लोगों का जीवन काफी आसान हो जाएगा।

सुविधाएं बढ़ती हैं, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पुरलिया जिले में लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सिटी गैस वितरण(सीजीडी) परियोजना की आधारशिला रखी। हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के दुर्गापुर से कोलकाता खंड (132 किलोमीटर) को भी राष्ट्र को समर्पित किया, इसे जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन के एक भाग के रूप में बिछाया गया है। यह प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा (पीएमयूजी) परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। इस पर 1190 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आ रहा है। यह पश्चिम बंगाल के पुरबा बर्धमान, हुगली और नादिया जिलों से होकर गुजर रहा है।

प्रधानमंत्री ने 1457 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली दुर्गापुर इस्पात ताप विद्युत केंद्र और दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर ताप विद्युत केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली का पुनरोद्धार-फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) को भी राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने पुरलिया में कोटशिला रेल लाइन (36 किलोमीटर) के दोहरीकरण के कार्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पश्चिम बर्धमान के तोपसी और पांडवेश्वर में सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत 380 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने दो सड़क ऊपरी पुलो (आरओबी) का भी उदघाटन किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में देश में घरेलू गैस कनेक्शनों की संख्या में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। एलपीजी घर-घर तक पहुंच गई। वन नेशन-वन गैस ग्रिड के दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत पश्चिम बंगाल सहित छह पूर्वी राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इन राज्यों में उद्योगों और रसोई तक सस्ती पाइप गैस पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में श्री मोदी ने कहा कि गैस की उपलब्धता से इस क्षेत्र में वाहन सीएनजी से चल सकेंगे और उद्योग गैस आधारित तकनीकों को अपना सकेंगे। दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र के राष्ट्रीय गैस ग्रिड का हिस्सा बनने पर संतोष जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे क्षेत्र के उद्योगों को लाभ होगा और पश्चिम बंगाल के लगभग 30 लाख घरों तक पाइप के जरिए सस्ती गैस पहुंचेगी। इससे लाखों परिवारों, विशेष रूप से माताओं और बहनों का जीवन आसान होगा। और हजारों लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा।

दुर्गापुर और रघुनाथपुर में प्रमुख इस्पात और विद्युत संयंत्रों को नई तकनीक के साथ उन्नत करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संयंत्रों में लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ये संयंत्र अब अधिक कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। देश के हर प्रयास को भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प से प्रेरित बताते हुए श्री मोदी ने सरकार के भविष्य के मार्ग : विकास के माध्यम से सशक्तिकरण, रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता के माध्यम से सुशासन को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इन मूल्यों को कायम रखते हुए पश्चिम बंगाल को भारत की विकास यात्रा का एक मजबूत इंजन बनाया जाएगा। ■

सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक में बोले श्री अमित शाह

समितियों को जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों के रूप में बदल रही सरकार

- भूमिहीन और पूंजीहीन व्यक्ति के लिए सहकारिता क्षेत्र से ही खुल रहा समृद्धि का रास्ता
- मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में पैक्स, डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंक, चीनी सहकारी समितियों और शासन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की
- समिति के सभी सदस्यों के अपने-अपने राज्यों में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने से सहकारिता को मिलेगा बल

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी समितियों को जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों के रूप में परिवर्तित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय प्रतिबद्ध है। देश के सहकारी तंत्र को परिवर्तनकारी बनाने के लिए सरकार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाई है और सहकारिता में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। इन विचारों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संसदीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। यह यूनिवर्सिटी भारत में सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को एकीकृत और मानकीकृत करेगी तथा सहकारी क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन प्रदान करेगी। सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय की 100 से अधिक पहलों पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा कि देश भर में दो लाख सहकारी समितियों की स्थापना का जो लक्ष्य रखा गया है, उस दिशा में अबतक 35,395 नई सहकारी समिति बन चुकी हैं। इनमें 6,182 बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (एमपैक्स) और 27,562 डेयरी कोऑपरेटिव एवं 1,651 मत्स्य सहकारी समितियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से अगले पांच वर्षों में सहकारी समितियों के नेतृत्व में दूध की खरीद को 50 प्रतिशत बढ़ाने के लक्ष्य की ओर भी तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक 15,691 नई डेयरी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं और 11,871 मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और 15 राज्यों में 25 मिल्क यूनियनों ने डेयरी सहकारी समितियों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

परंपरागत बीजों के लिए छोटे किसानों के साथ भी अनुबंध करेगी सरकार

सहकारिता को समाज के कमजोर वर्गों की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण मार्ग बताते हुए श्री शाह ने कहा कि भूमिहीन और पूंजीहीन व्यक्ति के लिए सहकारिता क्षेत्र से ही समृद्धि का रास्ता खुल रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र, कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी

समितियों का गठन किया गया है। जैविक उत्पादों, निर्यात और बीज क्षेत्रों में बनीं इन तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों का उद्देश्य सहकारी मूल्य श्रृंखला में पैमाने, गुणवत्ता और ब्रांडिंग को बढ़ाना है। श्री शाह ने कहा कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) भारत के परंपरागत बीजों के संरक्षण, संग्रहण और उत्पादन की दिशा में काम करती है, जिससे किसानों को उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि परंपरागत बीजों के लिए सरकार छोटे किसानों के साथ भी अनुबंध करेगी, जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) किसानों के ऑर्गेनिक उत्पादों की प्रमाणिकता, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उनकी मार्केटिंग सुनिश्चित कर रही है जिससे किसानों को उनके उत्पादों का अच्छा मूल्य मिल रहा है। इसीप्रकार, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) किसानों के उत्पादों को अतंरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जिसका पूरा मुनाफा किसानों को मिल रहा है।

राज्यों में डेयरी कोऑपरेटिव के मजबूत करने पर जोर

श्री शाह ने डेयरी सहकारी समितियों के सभी सदस्यों से अपने-अपने राज्यों में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे सहकारिता को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंक, चीनी सहकारी समितियों और शासन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की हैं। देश में सतत सहकारी विकास के लिए बनी राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 ने एक व्यापक रोडमैप प्रदान किया है। इसमें भारत सरकार की योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) और अन्य के साथ समन्वय भी शामिल हैं। श्री शाह ने कहा कि नई पालिसी के जरिए सहकारी इकोसिस्टम को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा।

नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी पर फोकस

सहकारिता मंत्रालय ने इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने और इसके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए पिछले चार वर्षों में की गई 100 से अधिक पहलों के बारे परामर्शदात्री समिति को जानकारी साझा की। मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि अबतक किए गए सभी नीतिगत पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र विकसित की गई है और इसके लिए अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तर समन्वय समिति, राज्य सहकारी विकास समितियां (एससीडीसी) और जिला सहकारी विकास समितियां (डीसीडीसी) गठित की गई हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सरकार ने पैक्स, डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंक, चीनी सहकारी समितियों और शासन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए जो महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं, उनमें डिजिटल सुधार, नीतिगत परिवर्तन, वित्तीय सहायता और संस्थागत क्षमता निर्माण आदि बेहद लाभकारी पहल शामिल हैं।

इस मौके पर समिति ने सहकारी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए अपने अहम सुझावों को साझा किया और सहकारिता मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में विकास, समानता और आत्मनिर्भरता के इंजन के रूप में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोल भी समिति के सदस्यों, सहकारिता मंत्रालय के सचिव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित थे। ■

यमुना के पुनर्जीवन के लिए समीक्षा बैठक में श्री अमित शाह ने कहा

जल प्रवाह बढ़ाने से बदलेगी यमुना की सूरत

सहकार जागरण टीम

- यमुना सफाई अभियान में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिलकर करें काम
- यमुना के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 2028 तक 1,500,000,000 गैलन प्रतिदिन तक बढ़ाने के दिए निर्देश
- ओखला के उपचारित जल को यमुना के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाए, जिससे नदी जल की गुणवत्ता बेहतर हो

देश में नदियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार संकल्पित है। इसके लिए नदी तटों की सफाई, वृक्षारोपण, जल संचयन और औद्योगिक कचरे पर नियंत्रण जैसे विभिन्न गतिविधियों को तेज किया गया है और सभी देशवासियों को जल की महत्ता एवं उसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना नदी की स्वच्छता के लिए कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में यमुना पुनर्जीवन को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने नदियों को स्वच्छ करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही कोशिशों के अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) का बजट बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। यमुना में पर्यावरणीय जल प्रवाह (ई-फ्लो) बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके हल निकालना होगा, जिससे कि यमुना के दिल्ली में प्रवेश के समय का जल प्रवाह बेहतर हो सके।

श्री शाह ने कहा कि यमुना नदी में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा जैसे राज्यों से भी अपशिष्ट के रूप में केमिकल आ रहा है, इसलिए इन सभी राज्यों को साथ मिलकर नदी को स्वच्छ करने के उपायों पर कार्य करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि यमुना पुनर्जीवन के लिए इन तीनों राज्यों के एसटीपी से निकल रहे जल की निरंतर व निष्पक्ष जांच हो और इसके लिए एसटीपी के आउटफ्लो की किसी थर्ड पार्टी से जरिए गुणवत्ता की परख भी की जानी चाहिए। यमुना की सफाई के साथ-साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता वृद्धि पर विशेष जोर देते हुए श्री शाह ने वर्ष 2028 तक एसटीपी क्षमता को 1,500,000,000 गैलन प्रतिदिन तक बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने ओखला के उपचारित जल को यमुना के डाउनस्ट्रीम में छोड़ने पर जोर दिया। इससे नदी के जल की गुणवत्ता बेहतर करने में मदद मिलेगी।

श्री शाह ने कहा कि दिल्ली में कई जलाशय हैं जिनमें दिल्ली सरकार को बरसाती पानी संग्रह करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन जलाशयों को विकसित करने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि डेयरी, गौशालाओं के उत्पादित अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। श्री शाह ने दिल्ली के अनधिकृत डेयरियों के प्रबंधन करने पर भी जोर दिया ।

श्री शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार को औद्योगिक इकाइयों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सतत एवं प्रभावी कदम उठाने चाहिए और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए ऐक्शन मोड में कार्य करना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के दो मुख्य ड्रेनों, नजफगढ़ और शाहदरा में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) को सुधारने की कार्ययोजना पर कार्य करने पर जोर देते हुए इसके लिए इन ड्रेनों की ड्रोन सर्वे कराने के भी निर्देश दिए। ■

पांच देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बोले

विदेशों में बसे भारतवंशियों को अपनी विरासत पर गर्व

सहकार जागरण टीम

पांच देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वहां बसे भारतीय मूल के लोगों के अपनी जड़ों से जुड़े रहने पर उनकी तारीफ की और भारत के साथ उनके प्रगाढ़ सांस्कृतिक-धार्मिक संबंधों को याद किया। कैरीबियन द्वीप त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचे श्री मोदी ने 180 साल पहले वहां गए भारतवंशी जिस प्रकार अब भी भगवान राम और रामचरितमानस से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में कहा, ' एक सौ अस्सी साल बीतल हो, मन न भुलल हो, भजन राम के, हर दिल में गूंजल हो।' अपने साथ सरयू का जल और राम मंदिर की कलाकृति लेकर गए श्री मोदी ने उसे त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला बिसेसर को भेंट किया और कहा, 'सरयू जी और पवित्र संगम का ये जल, आस्था का अमृत है। ये प्रवाहमान धारा है, जो हमारे मूल्यों को, हमारे संस्कारों को हमेशा जीवंत रखती है।'

- **भोजपुरी में बोल प्रधानमंत्री ने जीता भारतवंशियों का मन**
- **पीएम मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री को सौंपा सरयू का जल और राम मंदिर की कलाकृति**
- **चार देशों ने पीएम मोदी को प्रदान किया अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान**

त्रिनिदाद टोबैगो की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अयोध्या व नवनिर्मित राम मंदिर के बारे में संदेश दिया कि 'राम धामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिदित अति पावनि। 42 फीसद भारतवंशियों की आबादी वाले इस देश में वर्ष 1999 के बाद पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचे श्री मोदी को वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद व टोबैगो प्रदान किया गया।' वहां की प्रधानमंत्री कमला बिसेसर के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि, 'प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं।' यहां मौजूद अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए थे। बिहार की विरासत.. भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो.. बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है, 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से, नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे।' भारत को अवसरों की जमीन बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि कारोबार, पर्यटन, शिक्षा, हेल्थकेयर हर क्षेत्र में भारत बहुत कुछ दे सकता है। उन्होंने त्रिनिदाद व टोबैगो में रहने वाले छठी पीढ़ी के भारतवंशियों को ओसीआई कार्ड भी देने का ऐलान किया।

इसके पूर्व घाना पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को वहां का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहां की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने भारत और घाना के बीच ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया, जो स्वतंत्रता के लिए साझा संघर्षों और लोकतंत्र तथा समावेशी विकास के लिए समान प्रतिबद्धता के माध्यम से बना है। भारत में लोकतंत्र की गहरी और जीवंत जड़ों पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने भारत की विविधता और लोकतांत्रिक ताकत को विविधता में एकता की शक्ति के प्रमाण के रूप में इंगित किया। यह एक ऐसा मूल्य है जो घाना की अपनी लोकतांत्रिक यात्रा में प्रतिध्वनित होता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी और साइबर खतरों जैसी वैश्विक चुनौतियों को भी रेखांकित किया और वैश्विक शासन में विकासशील देशों की सामूहिक आवाज का आह्वान किया। इस संदर्भ में, उन्होंने भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने पर प्रकाश डाला। ■

अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव के रूप में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील में रहने वाले भारतीय समुदाय की सराहना की। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि वे किस तरह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भारत के विकास के प्रति भी बहुत भावुक हैं। इस दौरान ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए जाने पर श्री मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व व भावुकता का पल है। यह सम्मान भारत के प्रति ब्राजील की गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता का प्रमाण है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दशकों पुराना है। अब हम कृषि अनुसंधान और खाद्य प्रशंस्करण पर मिलकर काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग बढ़ रहा है। दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारा सहयोग न केवल ग्लोबल साउथ, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है।

57 वर्षों में किसी भारतीय शासनाध्यक्ष के रूप में अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत व अर्जेंटीना के संबंधों में अब गहराई आती जा रही है। भारत अर्जेंटीना के सबसे बड़े छह व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इसका द्विपक्षीय व्यापार लगभग पांच अरब अमेरिकी डॉलर है। अर्जेंटीना भारत को सोयाबीन तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत की ईवी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अर्जेंटीना के एक प्रमख साझेदार है। परमाणु सहयोग आपसी हित का एक और उभरता क्षेत्र है। दोनों देश परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक समझौता करने जा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भी भारत व अर्जेंटीना एकजुट हैं। यह यात्रा एक नई शुरुआत है, जो आपसी विश्वास को मजबूत करती है और सहयोग के नए रास्ते खोलती है। साझा आकांक्षाएं और आपसी सम्मान हमें एक-दूसरे के और करीब लाते हैं।

अपनी यात्रा के आखिरी चरण में नामीबिया पहुंचे श्री मोदी को वहां के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान वहां की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संस्थापकों द्वारा समर्थित लोकतांत्रिक मूल्य और सिद्धांत दोनों देशों में प्रगति के पथ को प्रकाशित करते रहेंगे। देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में नामीबिया की सरकार और जनता की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के प्रहरी के रूप में दोनों देशों से वैश्विक दक्षिण की बेहतरी के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत हमेशा अफ्रीका की प्रगति के लिए काम करेगा, जैसा कि उसने जी-20 की अध्यक्षता के दौरान किया था, जब अफ्रीकी संघ को इस समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया था। भारत क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देने और अफ्रीका के एजेंडा 2063 का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में बोले श्री अमित शाह

राज्यों के विकास से ही होगा विकसित भारत का निर्माण

- **वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सभी साथ मिलकर आगे बढ़ें**
- **मोदी सरकार में क्षेत्रीय परिषदें चर्चा के मंच की जगह सहयोग का इंजन बनीं**
- **क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 83 प्रतिशत मुद्दों का समाधान इसकी सार्थकता को दर्शाता है**
- **वर्ष 2004 से 2014 के बीच क्षेत्रीय परिषदों की 25 बैठकों के मुकाबले पिछले दस वर्षों में 63 बैठकें हुईं**

सहकार जागरण टीम

सहकारी संघवाद की सशक्त आधारशिला बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिषदों की कल्पना की गई थी और अब ये सलाहकारी भूमिका से आगे बढ़कर कार्रवाई योग्य मंच बन गई हैं। क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से हम केंद्र के साथ राज्यों और राज्यों के बीच के आपसी मुद्दों को काफी हद तक हल करने में सफल हुए हैं। ये परिषदें अब चर्चा मंच की जगह सहयोग का इंजन बन गई हैं। इन विचारों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक के दौरान साझा किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सहकारी संघवाद के आधार पर टीम भारत की कल्पना देश के सामने रखी है। इसके तहत राज्यो के विकास के माध्यम से भारत का विकास और वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ रहें हैं। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद को संविधान में आधार दिया गया है और उसी के तहत क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें आयोजित होती हैं। श्री शाह ने

कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच क्षेत्रीय परिषदों की केवल 25 बैठकें हुई थीं, जबकि वर्ष 2014 से 2025 के दौरान इन बैठकों के आयोजन में अपूर्व गति आई है और इस दौरान दोगुने से भी अधिक बढ़कर 63 बैठकें हो चुकी हैं और ये अधिक परिणामदायक बनी हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रतिवर्ष 2-3 बैठकों से आगे बढ़कर प्रतिवर्ष लगभग छह बैठकों के आयोजन तक पहुंच गए हैं। इन बैठकों में कुल 1580 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से 1287 यानी 83 प्रतिशत मुद्दे हल कर लिए गए हैं, जो कि क्षेत्रीय परिषदों की सार्थकता को दर्शाता है।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। बैठक में झारखंड, ओडिशा और बिहार के मुख्यमंत्रियों और पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री सहित सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में राष्ट्रीय महत्त्व के व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इनके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के नियत दायरे में ब्रिक-एंड-मोर्टार बैंकिंग सुविधा, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का कार्यान्वयन तथा पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, शहरी प्लानिंग एवं सहकारिता व्यवस्था के सुदृढीकरण सहित क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित के विभिन्न मुद्दे शामिल रहे। इस बैठक में मसंजौर बांध, तैयबपुर बराज और इंद्रपुरी जलाशय से संबंधित काफी समय से लंबित जटिल मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही, बिहार के विभाजन के समय से ही लंबित अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्तियों और देनदारियों के बिहार व झारखंड राज्यों के बीच विभाजन से संबंधित मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई और उनके समाधान की दिशा में आपसी सहमति से निर्णायक कदम उठाए गए।

श्री शाह ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों पर जल्द से जल्द पूर्ण अमल की दिशा में पूर्वी राज्यों को और अधिक प्रयास करना चाहिए। इन राज्यों में नार्कोटिक्स पर नकेल कसने की दिशा में भी अधिक कार्य करने की जरूरत है, जिसके लिए जिला स्तरीय राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी क्षेत्र के चारों राज्यों को कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में परंपरागत और स्ट्रक्चरल ढांचे से बाहर निकल कर आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए।

भक्ति, ज्ञान, संगीत, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्रांति की भूमि है पूर्वी भारत

श्री शाह ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमि का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस भूमि से भगवान बिरसा मुंडा सहित कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के आंदोलनों का नेतृत्व किया है। पूरा पूर्वी भारत भक्ति, ज्ञान, संगीत, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्रांति की भूमि रहा है और शिक्षा के मूल आदर्श स्थापित करने में पूर्वी भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद, बिरसा मुंडा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद व बाबू जगजीवन राम सहित कई विभूतियों ने इसी भूमि से देश को अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व दिया है। श्री शाह ने कहा कि सांस्कृतिक चेतना, भक्ति चेतना और क्रांति तीनों का संगम इसी भूमि पर हुआ है।

श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने अपनी वीरता, सटीकता और जांबाजी का अनुभव पूरी दुनिया को कराया है और उनके साहस और पराक्रम के लिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद सेनाओं की वीरता के लिए सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए भारत का आतंकवाद के अंत का मजबूत इरादा पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध सभी राज्यों की एकजुटता और सुरक्षा बलों की बहादुरी से हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है और हम 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर के रहेंगे। बिहार, झारखंड और ओडिशा काफी हद तक नक्सलवाद से मुक्त हो गए हैं। ■

आदि तिरुवथिरई महोत्सव में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

काशी-तमिल और सौराष्ट्र तमिल संगमम से एकता का बंधन हो रहा मजबूत

- चोल शासकों ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया
- चोल साम्राज्य की विरासत भारत की पहचान और गौरव का पर्याय
- 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र के साथ भारत बढ़ रहा आगे
- भारत के स्वर्ण काल में से एक चोल युग अपनी दुर्जेय सैन्य शक्ति के लिए विख्यात

सहकार जागरण टीम

चोल शासकों ने भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया, आज हमारी सरकार चोल युग के उन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ा रही है। काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम सदियों पुराने एकता के बंधन को और मजबूत कर रहे हैं। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवथिरई महोत्सव को संबोधित करते हुए कही। श्री इलैयाराजा के संगीत और ओधुवरों के पवित्र मंत्रोच्चार के साथ, राजराज चोल की पावन भूमि में दिव्य शिव दर्शन के माध्यम से अनुभव की गई गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस आध्यात्मिक वातावरण ने आत्मा को गहराई से प्रभावित किया है।

भगवान शिव की भक्ति में निहित चोल विरासत को अमर बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, राजराजा चोल और राजेंद्र चोल की विरासत भारत की पहचान और गौरव का पर्याय है। चोल साम्राज्य का इतिहास और विरासत भारत की वास्तविक क्षमता का प्रतीक है। यह विरासत एक विकसित भारत के निर्माण की राष्ट्रीय आकांक्षा को प्रेरित करती है।

चोल साम्राज्य द्वारा भारत की लोकतांत्रिक

परंपराओं को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां इतिहासकार लोकतंत्र के संदर्भ में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, वहीं चोल साम्राज्य ने कुदावोलाई अमाइप्पु तंत्र के माध्यम से सदियों पहले लोकतांत्रिक चुनाव पद्धतियों को लागू किया था। श्री मोदी ने बताया कि आज दुनिया में अक्सर जल प्रबंधन और पारिस्थितिकी संरक्षण पर चर्चा होती रहती है, लेकिन भारत के पूर्वजों ने इन मुद्दों के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था। जहां कई राजाओं को दूसरे क्षेत्रों से सोना, चांदी या पशुधन प्राप्त करने के लिए याद किया जाता है, वहीं राजेंद्र चोल को पवित्र गंगा जल लाने के लिए जाना जाता है। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल लाकर दक्षिण में प्रवाहित किया। उन्होंने 'गंगा जलमयं जयस्तंभम' वाक्यांश का उल्लेख करते हुए बताया कि जल को चोल गंगा झील में प्रवाहित किया जाता था, जिसे अब पोन्नेरी झील के नाम से जाना जाता है।

राजेंद्र चोल द्वारा स्थापित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, जो आज भी विश्व में वास्तुशिल्प के एक चमत्कार के रूप में जाना जाता है, का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मां कावेरी की भूमि पर गंगा का उत्सव भी चोल साम्राज्य की विरासत है। इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में, काशी से एक बार फिर गंगा जल तमिलनाडु लाया गया है और एक औपचारिक अनुष्ठान किया गया। काशी के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में, प्रधानमंत्री ने मां गंगा के साथ अपने गहरे भावनात्मक जुड़ाव को साझा करते हुए कहा कि चोल राजाओं से जुड़े प्रयास और कार्यक्रम एक पवित्र प्रयास–'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रतीक हैं, जो इस पहल को एक नई ऊर्जा और गति प्रदान करते हैं।

चिदंबरम नटराज मंदिर के दीक्षितों के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस मंदिर में भगवान शिव की नटराज रूप में पूजा की जाती है। नटराज का यह रूप भारत के दर्शन और वैज्ञानिक आधार का प्रतीक है।

नयनमार संतों की विरासत, उनके भक्ति साहित्य, तमिल साहित्यिक योगदान और अधीनमों के आध्यात्मिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत की शैव परंपरा ने राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चोल सम्राट इस सांस्कृतिक विकास के प्रमुख निमार्ता थे और तमिलनाडु जीवंत शैव विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है।'

अस्थिरता, हिंसा और पर्यावरणीय संकट जैसी चुनौतियों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शैव दर्शन इनके सार्थक समाधान के मार्ग बताता है। उन्होंने तिरुमूलर की शिक्षाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने 'अनबे शिवम', जिसका अर्थ है 'प्रेम ही शिव है' लिखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि विश्व इस विचार को अपना ले, तो कई समस्याओं का समाधान अपने आप हो हो सकता है। भारत 'एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य' के आदर्श वाक्य के जरिए इस दर्शन को आगे बढ़ा रहा है।

'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र के साथ भारत के आगे बढ़ने की बात कहते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में राष्ट्र ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मिशन मोड में काम किया है। विदेशों से प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों को वापस भारत लाया गया है। वर्ष 2014 से अब तक विश्व के विभिन्न देशों से 600 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां वापस लाई गई हैं, इनमें से 36 कलाकृतियां विशेष रूप से तमिलनाडु की हैं। नटराज, लिंगोद्भव, दक्षिणामूर्ति, अर्धनारीश्वर, नंदीकेश्वर, उमा परमेश्वरी, पार्वती और संबंदर सहित कई बहुमूल्य विरासत वस्तुएं एक बार फिर इस भूमि की शोभा बढ़ा रही हैं।

चोल काल में हुए आर्थिक और सामरिक विकास को आधुनिक भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बताते हुए प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि राजराजा चोल ने एक शक्तिशाली नौसेना की स्थापना की, जिसे राजेंद्र चोल ने और मजबूत किया। चोल काल स्थानीय शासन प्रणालियों के सशक्तिकरण और एक मजबूत राजस्व ढांचे के कार्यान्वयन सहित प्रमुख प्रशासनिक सुधारों का साक्षी बना। भारत ने व्यापार, समुद्री मार्गों के उपयोग और कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से सभी दिशाओं में तेजी से प्रगति की। चोल साम्राज्य नए भारत के निर्माण के लिए एक प्राचीन रोडमैप के रूप में कार्य कर रहा है। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपनी नौसेना और रक्षा बलों को मजबूत करना चाहिए, नए अवसर तलाश करने चाहिए और अपने मूल मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। देश इसी दृष्टि से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहा है।

इस बात पर जोर देते हुए कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व ने इसे अपनी संप्रभुता के विरुद्ध किसी भी खतरे का भारत द्वारा दृढ़ और निर्णायक जवाब के रूप में देखा है। इस ऑपरेशन ने एक स्पष्ट संदेश दिया है– आतंकवादियों और देश के दुश्मनों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के लोगों में एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न किया है और पूरा विश्व इसे देख रहा है। ■

मसूरी में सहकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक

सहकारिता के माध्यम से समृद्ध हो रहे किसान

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र में व्यापक विकास के साथ विकसित भारत के मुख्य आधार बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता ग्रामीण समृद्धि का आधार बन रही है और इसका लक्ष्य देश भर के प्रत्येक गांव तक सहकारिता की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। इन्हीं विचारों के साथ केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी, मसूरी में आयोजित हुई।

मसूरी सम्मेलन में ग्राम-स्तरीय सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास को गति मिली

सहकारिता के माध्यम से जमीनी स्तर पर सहकारी विकास को तीव्र करने के दृढ़ संकल्प के साथ सहकारिता में भूमिहीन किसानों के समावेश और व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए देश के सभी गांवों में सहकारी समितियों की स्थापना के लिए मिशन-मोड में कार्रवाई का आह्वान किया गया। सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सहकारी समितियों की सदस्यता बढ़ाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पैक्स के संशोधित मॉडल बाइलॉज के आधार पर देश के सभी जिलों के सभी गांवों में सहकारी समितियों की स्थापना होने पर सहकारिता का फलक सर्वसमावेशी हो जाएगा।

उन्होंने सभी हितधारकों को नए मानक स्थापित करके और नवीन दृष्टिकोण अपनाकर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष -2025 के अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सरकार के एक पेंड़ मां के नाम 2.0 जैसी अनूठी पहलों को लागू करने और सहकारी सिद्धांतों पर केंद्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया और हितधारकों से मिशन मोड में काम करने और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समावेशी सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ सहकारी अधिकारियों ने बैठक में सहकारी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक मानव संसाधन प्रथाओं और नेतृत्व मॉडल को अपनाने का आग्रह किया गया। सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार बंसल ने शहरी सहकारी बैंकों पर गठित कार्यबल को पुनर्जीवित करने, साझा सेवा इकाई में राज्य सहकारी बैंकों की भागीदारी बढ़ाने और राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के साथ जुड़ाव को गहरा करके शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के जरिए सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग, बेहतर प्रशासन, प्रौद्योगिकी अपनाने और वित्तीय स्थिरता पर जोर दिया गया।

इस दौरान सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा के जरिए इसमें नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल), नेशनल कोऑपरेटिव आर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल), भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड) जैसे शीर्ष संगठनों की भूमिका पर चर्चा की गई और सहकारी नेटवर्क के माध्यम से अनाज भंडारण योजना के क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर प्रगति और अभिसरण पहलों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को मजबूत करने के प्रयासों का भी मूल्यांकन किया गया। राष्ट्रीय सहकारी दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने और सार्वभौमिक पहुंच को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए ग्रामीण व आर्थिक विकास के इंजन के रूप में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए अंतर-राज्यीय ज्ञान साझाकरण, अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण और रणनीतिक योजना की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही, निष्क्रिय समितियों को समाप्त करने पर जोर देते हुए राज्यों और संस्थानों ने सहकारी सुधारों में तेजी लाने, जमीनी स्तर पर नेतृत्व को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने का सामूहिक संकल्प लिया कि सहकारी समितियां समावेशी और सतत राष्ट्रीय विकास की प्रेरक शक्ति बनें। ■

सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता को बढ़ावा

सहकार जागरण टीम

भारत में 100 साल से भी अधिक समय से जारी सहकारिता आंदोलन का लोगों के जीवन में बदलाव लाने में अहम भूमिका रही है। खासकर देश के ग्रामीण इलाकों में सहकारिता से लोगों को आर्थिक ताकत मिली। लेकिन वर्ष 2014 से पहले अपनी कुछ खामियों जैसे अप्रासंगिक कानून, सरकारी दखल, भ्रष्टाचार व कुप्रबंधन के चलते यह अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से हासिल करने में असफल साबित हो रही थी। वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद इसमें कई बड़े बदलाव आए और इस बदलाव में श्री अमित शाह की अहम भूमिका रही। सबसे प्रमुख बदलाव के रूप में वर्ष 2021 में कृषि से अलग कर सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और श्री अमित शाह को इसका नेतृत्व करने का जिम्मा दिया गया।

इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना, पारदर्शिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। सहकारिता मंत्री के रूप में श्री शाह ने सहकारी समितियों के विस्तार की योजना बनाई। इसके लिए राष्ट्रीय डेटा बेस बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य उन गांवों का पता लगाना है, जहां एक भी सहकारी संस्था नहीं है, ताकि वहां सहकारी समिति का गठन किया जा सके। श्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगले पांच वर्ष में हर गांव में कम से कम एक सहकारी समिति होगी।

बदलाव के क्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। पारदर्शिता व कुशलता के लिए इसका डिजिटलीकरण किया गया। कृषि ऋण प्रदान करने के साथ अब ये किसानों को बीज, उर्वरक प्रदान करेंगी और बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाएंगी। वर्ष 2014 के बाद नई सरकार ने सहकारी बैंकों व डेयरी क्षेत्र में सुधार के लिए भी कदम उठाए। सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार मानते हुए सहकार से समृद्धि पर जोर दिया गया। इसके लिए सरकार ने कृषि के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन व हस्तशिल्प को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान कानूनी व प्रशासनिक सुधार भी किए गए। अप्रासंगिक कानूनों में बदलाव कर सहकारी समितियों में सरकारी हस्तक्षेप कम किया गया। इससे समितियों की स्वायत्तता को बढ़ावा मिला और वे बिना किसी हस्तक्षेप के अपने कार्यों को अंजाम दे रही हैं। निजी क्षेत्र से मुकाबले के लिए लिए इसे पेशेवर रूप से कुशल बनाया गया।

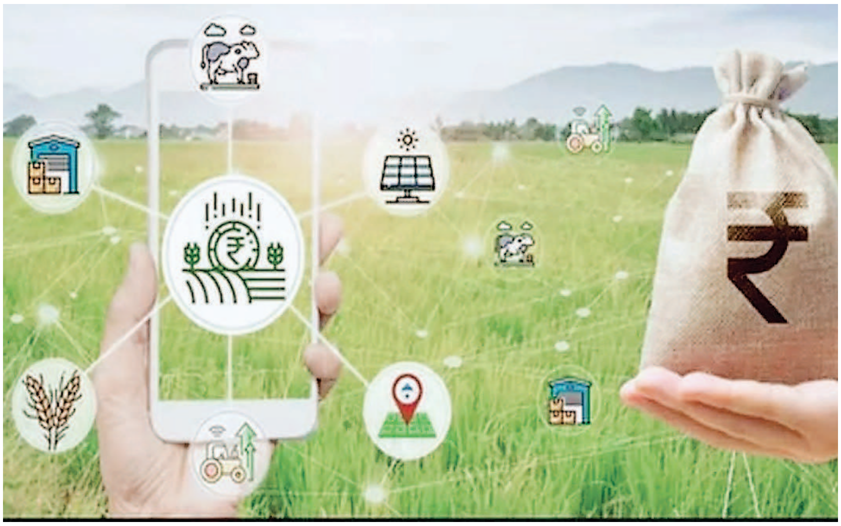

▶▶ अप्रासंगिक कानूनों में परिवर्तन कर सरकारी हस्तक्षेप को कम किया गया

श्री अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में भारी बदलाव आया है। डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया है। एक राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार किया गया है। इसके जरिए सहकारी समितियों की खूबियों व खामियों का पता लगाकर इनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया गया है। श्री शाह के नेतृत्व में सहकारी डेयरी व उर्वरक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अब देश में दूध व उर्वरकों की कोई कमी नहीं रह गई है। मांग के अनुरूप उपभोक्ताओं व किसानों तक दूध व उर्वरकों की आपूर्ति हो रही है। इससे खेती, किसानी खूब फल फूल रही है।

सहकारिता के क्षेत्र में श्री शाह के तीन दशक पुराने अनुभव का लाभ अब देश को राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है। उन्होंने 1990 के दशक में अपने नेतृत्व में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक को घाटे से उबारकर लाभ में पहुंचाया था। अब उनकी अगुआई में सहकारी क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का आधुनिकीकरण, डेयरी व बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और अप्रासंगिक हो चुके पुराने कानूनों में बदलाव इसका ज्वलंत उदाहरण है। ■

ताड़ला रामपुर की सहकारी समिति ने सफलता का बनाया नया कीर्तिमान

सहकार जागरण टीम

भारत में सहकारिता की समृद्ध परंपरा रही है। सामाजिक-आर्थिक विकास में सहकारी समितियों का अहम योगदान रहा है। विशेषकर ग्रामीण समुदाय के जीवन में बेहतरी लाने के लिए इन समितियों ने सराहनीय कार्य किया है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले की एरगटला मंडल की ताड़ला रामपुर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) ने अपने कार्यों से सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मात्र एक दशक में ताड़ला पैक्स का कारोबारी दायरा 30 गुना तक बढ़ गया है। समिति के वितरित कर्ज की शत प्रतिशत वापसी हुई है, जिससे समिति को अच्छा लाभ मिला है। समिति ने गांवों में जरूरत की प्रत्येक सुविधा उपलब्ध कराई है। ग्रामीण बुनियादी ढांच के निर्माण में यहां की सहकारी समिति का कार्य उल्लेखनीय है।

दस साल में 30 गुना तक बढ़ा टर्नओवर

20 दिसंबर 1960 को चार गांवों ताड़ला रामपुर, गुम्मिरियाल, डोमचंदा, ताड़ापकल की सेवा के लिए गठित समिति विविध क्षेत्रों में कार्य कर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। समिति का टर्नओवर पिछले दस साल में 30 गुना तक बढ़ गया है। विकास कार्यों और अपने सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाओं से सुदूर गांव में स्थित इस समिति की पहचान राज्य की सर्वश्रेष्ठ सहकारी समितियों में होने लगी है।

सदस्यों को प्रदान कर रही विविध सेवाएं

समिति अपने समक्ष आने वाली चुनौतियों

का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है और सफलता के नए मानक स्थापित कर रही है। समिति अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रही है। विशाल मीटिंग हॉल, बैंकिंग काउंटर, विशाल परिसर, शॉपिंग सेंटर, फंक्शन हॉल, हाल ही में खोला गया दूध ठंडा करने का केंद्र, राइस मिल, उर्वरक व अनाज भंडारण गोदाम आदि के जरिए समिति जहां अपने सदस्यों को सुविधाएं प्रदान कर रही है, वहीं इन सेवाओं के जरिए खुद भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है।

समिति के पास तीन गांवों यानी गुम्मिरियाल, डोमचंदा, तडापकल में अनाज व उर्वरक स्टोर करने के लिए बड़े गोदाम हैं। इसी प्रकार इन गांवों में उसके पास अन्य बहुमूल्य संपत्तियां हैं। इसके जरिए भी उसे कमाई होती है और वह अपने संसाधनों का बढा पाने और लोगों को सेवा प्रदान करने में सक्षम हो पा रही है।

ऋण की शत-प्रतिशत वसूली

खास बात यह है कि समिति ने अपने सदस्यों को जो ऋण प्रदान किया है, उसकी शत-प्रतिशत वसूली करने में सफल रही है। ऐसा करके उसने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार द्वारा ऋण का पूरा भुगतान करने वालों को प्रोत्साहन के रूप में घोषित 5000 रुपए की राशि समिति के सदस्यों को प्रदान की गई। प्रोत्साहन योजना के तहत समिति के सदस्यों को 31 लाख रुपए का लाभ मिला।

समिति जहां अपने सदस्यों को फसल ऋण, दीर्घकालीन ऋण, स्वर्ण आभूषणों पर ऋण, जमा पर ऋण प्रदान कर रही है, वहीं खाद, बीज और कीटनाशकों के व्यवसाय में भी शामिल है। नित नई सेवाएं शुरू कर और सुविधाएं प्रदान कर समिति आर्थिक लाभ हासिल कर रही है।

खेती के साथ अन्य जरूरतों के लिए प्रदान करती है ऋण

समिति ने अपने सदस्यों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए, धान काटने की मशीन खरीदने के लिए, हल्दी उबालने की मशीन खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया है, साथ ही घर बनाने और भेड़-बकरी खरीदने के लिए ऋण दिया है। कार व अन्य वाहन खरीदने के लिए भी समिति की ओर से ऋण प्रदान किया जाता है।

समिति मक्का समेत अन्य अनाज की खरीद के लिए मार्कफेड और एफसीआई के एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। इससे भी समिति को पर्याप्त कमीशन प्राप्त हुआ है। पैक्स ने बैंकिंग और इंश्योरेंस व्यवसाय में अभूतपूर्व कार्य किया है। इनके बैंकों में लॉकर की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इस प्रकार अपनी कुशल कार्यप्रणाली और प्रभावशाली सेवाओं के जरिए समिति विकास की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है और अपने सदस्यों के दिलों में जगह बनाती जा रही है। ■

सहकारी कृषि में नए मानक स्थापित कर रहा समृद्धि एफपीओ

सहकार जागरण टीम

भारत के सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने और किसानों को समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने अबतक करीब 1,900 एफपीओ का गठन करके सहकारी विकास को गति प्रदान किया है। इनमें महाराष्ट्र के सतारा जिले का 'समृद्धि एफपीओ' ने एक आदर्श मानक स्थापित किया है और प्रगतिशील कृषि परिदृश्य में नवाचार व उत्कृष्टता का एक सशक्त मॉडल बना है। यह किसानों को सशक्त बनाने के एनसीडीसी के मुहिम को सफल बना रहा है। चार वर्षों से भी कम समय में इस संगठन ने न केवल वित्तीय स्थिरता हासिल की है, बल्कि सहकारी क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्ता और किसान सशक्तिकरण का नया मानक स्थापित करते हुए तेजी से सफल सहकारी कृषि के एक मॉडल के रूप में उभरा है।

समृद्धि एफपीओ 750 शेयरधारक सदस्यों के एक विविध कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 98 छोटे किसान, 542 सीमांत किसान और 57 काश्तकार शामिल हैं। इनमें 330 महिला किसान भी शामिल हैं और सात आदिवासी समुदायों से हैं, जो संगठन की समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस एफपीओ ने प्रत्यक्ष सदस्यता से आगे बढ़कर अपने प्रभाव का विस्तार किया है, जिससे पूरे क्षेत्र में 4,500 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। 30 लाख रुपए की पर्याप्त शेयर पूंजी और एनसीडीसी से क्रमशः 15 लाख रुपए और 13.50 लाख रुपए का इक्विटी अनुदान और प्रबंधन लागत सहायता प्राप्त करके समृद्धि एफपीओ ने इतने कम समय में ही 3.32 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल किया है।

नवाचारों के जरिए किसानों का अग्रणी हितकारक

समृद्धि एफपीओ ने अपनी पेटेंट प्राप्त जैविक फॉस्फोमैन्योर उत्पादन सुविधा के साथ खुद को एक नवाचार अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। यह संगठन 4,000 टन की कुल क्षमता के साथ जैविक खाद का उत्पादन और मार्केटिंग करता है, जिससे 1,200 किसानों को सीधे लाभ होता है। कृषि विभाग के साथ मिलकर काम करते हुए इस एफपीओ ने बीज उत्पादन में कदम रखा है और उल्लेखनीय सफलता के साथ 11.90 टन गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन किया है, जिससे 13.06 लाख रुपए का कारोबार हुआ और 46 किसान सदस्यों को लाभ हुआ। यह पहल एफपीओ की तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करते हुए किसानों को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करती है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में समृद्धि एफपीओ ने सॉल्वेक्स संयंत्र को सीधे 168 टन सोयाबीन की आपूर्ति करके प्रत्यक्ष बाजार संपर्क स्थापित किया और इससे 85 लाख रुपए के कारोबार के जरिए 350 किसान सदस्यों को लाभ मिला। इससे बिचौलियों को खत्म करने और किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने की संगठन की क्षमता भी प्रदर्शित हुई।

इस एफपीओ ने कई उत्पाद श्रेणियों में मूल्य संवर्धन में सफलतापूर्वक कदम रखा है, जिसमें हल्दी प्रसंस्करण मुख्य है। 'समृद्धि' हल्दी के अचार और हल्दी पाउडर का निर्माण और मार्केटिंग करता है, जिससे कच्चे माल का मूल्यवर्धन होता है। संगठन ने आमों के लिए प्रत्यक्ष बिक्री चैनल स्थापित किए हैं, जिससे किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके और बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। इस एफपीओ की महिला समूहों ने कलात्मक चॉकलेट उपहार वस्तुएं विकसित की हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है और उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाई जा रही है। ■

श्री दिलीप संघाणी

सहकारिता के चार वर्षों की नायाब पहलें

सहकारिता को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को पूरा करने में केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। नये सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद के इन चार वर्षों में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। श्री शाह के नेतृत्व में जहां सहकारिता की खामियों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल दुरुस्त किया गया वहीं सहकारिता को नई दिशा देने के लिए उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। इसे सहकारिता की दूसरी क्रांति कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस दौरान सहकारिता में 60 से अधिक महत्वपूर्ण पहलें की गई है।

सहकारी संस्थाओं का डेटाबेस तैयार करने में केंद्रीय मंत्री श्री शाह के नेतृत्व में मंत्रालय का अथक परिश्रम सराहनीय रहा है। मॉडल बायलॉज से पैक्स से अपेक्स तक सुधार दिखा है। देश में सहकारिता को हर गांव तक पहुंचाने के लिए कुल दो लाख अतिरिक्त पैक्स के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कृषि, डेयरी और मत्स्य के पैक्स शामिल हैं।

सहकारिता में पारदर्शिता और कार्यदक्षता लाने के लिए पैक्स कंप्युटरीकरण को द्रुत गति से लागू किया गया। सहकारिता के पुनरोद्धार का कार्य श्री शाह ने राज्यों को साथ लेकर पूरा किया। पुराने पड़ चुके सहकारी कानूनों में यथोचित सुधार कर नये प्रावधान लाए गए हैं। सहकारिता में कानूनी सुधार के तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में आवश्यक संशोधन किए गए। सहकारिता में चुनाव के लिए अलग से केंद्रीय सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

पैक्स को सशक्त करने के लिए उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ा गया, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को शामिल किया गया है। सहकारिता से युवाओं को जोड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सहकारिता में प्रशिक्षित कुशल युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जिसमें इसी सत्र से शिक्षण कार्य शुरू होने जा रहा है। यह विश्वविद्यालय सहकारी प्रशासन, नेतृत्व, उद्यमिता, डिजिटल प्रबंधन, और नीति-निर्माण जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों और सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। सहकारी विश्वविद्यालय के माध्यम से सहकारी बैंक, विपणन संघ, आवास समितियों, कृषि सेवा समितियों और अन्य क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

सरकारी चीनी मिलों की समस्याओं का निराकरण करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह ने उन्हें निजी व सार्वजनिक चीनी मिलों के समान अवसर प्रदान किए हैं। इनकन टैक्स प्रणाली को तर्कसंगत बना दिया गया है। उनकी आर्थिक चुनौतियां दूर कर दी गईं।

राष्ट्रीय स्तर की तीन सहकारी सोसाइटियां बीज, निर्यात और आर्गेनिक्स का गठन किया गया, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलने लगी है। देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर सहकारिता क्षेत्र ने बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए दुनिया की सबसे बड़ा अन्न भंडारण योजना को हाथ में लिया है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसकी पायलट परियोजना के पूरा होने के बाद पहले चरण का प्रारंभ कर दिया गया है। किसानों की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उल्लेखनीय पहल की है। इसके तहत सहकारी संस्थाओं को किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का दायित्व दे दिया है। नैफेड और एनसीसीएफ जैसी सहकारी संस्थाएं दलहन व तिलहन की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने लगी हैं

सरकार की पहल पर सहकारी बैंकों को सार्वजनिक व निजी बैंकों जैसी सहूलियत मिलने लगी हैं। उन्हें जहां नई शाखाएं खोलने की सुविधा मिली है वहीं उनकी कारोबारी गतिविधियों को विस्तार मिला है। एनसीडीसी के ऋण वितरण का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इसका लक्ष्य पौने दो लाख करोड़ रुपए के पास पहुंचने का अनुमान है। इससे सहकारी संस्थाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। सहकारिता मंत्रालय ने इन चार वर्षों में 60 से अधिक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसे देशभ की सहकारी संस्थाएं लाभान्वित हो रही हैं। भारत में सहकारी आंदोलन की एक समृद्ध और प्रभावशाली परंपरा रही है। इसने विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में वर्तमान में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 29 करोड़ देशवासियों की सदस्य के रूप में सहभागिता है। ये समितियां कृषि उत्पादन, ग्रामीण वित्त, आवास, मार्केटिंग, उपभोक्ता सेवा, डेयरी सेक्टर, मत्स्य पालन और अन्य उद्योगों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। ■

अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई), नई दिल्ली में भारतीय डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, छत्तीसगढ़ व राजस्थान आदि विभिन्न राज्यों की डेयरी सहकारी समितियों के कुल 75 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

देश के कृषि विपणन सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम के दौरान एनसीसीई ने विभिन्न राज्यों के 55 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया, जहां समितियों से संबंधित जीएसटी व अन्य कराधान नीतियों, व्यवसाय विकास योजना के तहत तकनीकों एवं ब्रांडिंग, मार्केटिंग व प्रचार के साथ समितियों के प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया।

महिलाओं के उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशल को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता और व्यवसाय स्वामित्व को प्रोत्साहित करके उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से एनसीसीई, नई दिल्ली में महिला सहकारी प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, असम, सिक्किम और मणिपुर राज्यों से 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। एनसीयूआई के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी ने सहकारी आंदोलन और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के महत्व पर जोर दिया।

सहकारी संस्थाओं को रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने सहकारिता क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सहकारिता में दक्षता और समावेशिता बढ़ाने के लिए विशेष पहलों पर जोर दिया गया।

एनसीसीई ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के सहयोग से सहकारी क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के बीच क्षमता निर्माण और कानूनी समझ को बढ़ावा देने के लिए सहकारी कानून और प्रथाओं में दो सप्ताह के सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल की समितियों और महासंघों के 23 प्रतिनिधियों के साथ सहकारी शासन और प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों, कानूनी अधिकारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इसमें भागीदारी की।

भारत में 'भारतीय ऋण एवं बैंकिंग सहकारी समितियों का सहकारी शिक्षण भ्रमण' कार्यक्रम के तहत इंडोनेशिया, जॉर्डन, नेपाल, श्रीलंका और फिलिस्तीन के सात सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने एनसीयूआई, नई दिल्ली का दौरा किया। आईसीए-एपी क्रेडिट एवं बैंकिंग समिति (आईसीसीबी) ने राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ (नेफकार्ड) के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया।

हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनीं, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10 हजार एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है, कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है।

- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (CEAS-LMS) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक: राजीव शर्मा

Postal Registration No: DLHIN/25/A0141
Published on 15.04.2024 Applied for Registration/ Exempted

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ